

याष्ट्रदोही फार्नायर और महबूबा को कब होगी सजा

विपक्षी होने के नाते भाले ही फरूख अब्दुला और महबूबा मुफ्ती को सरकार के खिलाफ बोलने और कोसने का हक है। लेकिन पिछले लम्बे अरसे से जिस तरह के बयान इन दोनों नेताओं के राष्ट्र के विरोध में आ रहे हैं उससे सरकार ही नहीं आम जनमानस में इनके प्रति कोश्च उपन मान रहा है। केन्द्र सरकार भले ही बोट बैंक या फिर किन्हीं अन्य कारणों से इनके खिलाफ राष्ट्रदेह का मुकदमा दर्ज कर इन्हें जेल न भेज रही हो लेकिन जिस तरह के बयान लगातार इन नेताओं द्वारा भारत के खिलाफ दिये जा रहे उसके तहत इन पर राष्ट्रदेह का मुकदमा तो बनता ही है। आखिर ऐसे किसी फैसले के विरोध में खड़े होकर चीज़ की मदद लेने अथवा भारतीय ध्वज को न उठाने की बातें करने वाले किस मुहं से यह कह सकते हैं कि वे राष्ट्रविरोधी नहीं हैं? ये हरकतें तो साफ तौर पर राष्ट्रविरोधी ही हैं। फरूख अब्दुल्ला यह भी सफाई दे रहे हैं कि उनकी लड़ाई मजहबी नहीं है, लेकिन उनका रुख-रवैया यही साबित कर रहा है कि वह हुरियत कांग्रेस की तरह से अपनी अलगाववादी राजनीति को मजहबी रंग दे रहे हैं। वास्तव में इसी कारण वह जम्मू क्षेत्र के लोगों की आकांक्षाओं की कहीं कोई परवाह नहीं कर रहे हैं। केन्द्र सरकार की दरियादिली कहे या फिर मजबूरी कि फरूख अब्दुला यहाँ तक बयान दे चुके हैं कि कश्मीर भारत के बाप का नहीं है। जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 की बहाली की मांग करने वाले कश्मीर आधारित राजनीतिक गुटों की ओर से तथाकथित गुपकार गठबंधन का गठन उसी तरह की एक शरारत भरी कवायद है, जैसे हुरियत कांग्रेस के नाम पर की गई थी। इस गुपकार गठबंधन का भी वही हश्त होगा, जो आतंकपरस्त हुरियत कांग्रेस का हुआ, क्योंकि उसके नेता और खासकर फरूख अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती भी पाकिस्तान एवं चीन की भाषा बोल रहे हैं और वह भी निहायत बेशर्मी के साथ। गुपकार गठबंधन के अध्यक्ष के रूप

में फरूक अब्दुल्ला का यह कहना देश-तुनिया की आंखों में धूल झांकने के अलावा और कुछ नहीं कि हम भाजपा विरोधी हैं, देश विरोधी नहीं। महबूबा और अब्दुल्ला बड़ी चतुराई से यह भूल रहे हैं कि अनुच्छेद 370 को खत्म करने का फैसला दो तिहाई बहुमत से संसद ने लिया था। केवल कश्मीर आधारित राजनीतिक गुटों की ओर से सविधान के अस्थायी अनुच्छेद 370 की वापसी का राग अलापना यही बताता है कि वे घाटी को देश और यहां तक कि जम्मू से भी अलग मानते हैं। उनके इस मुगालते को दूर करने की सख्त जरूरत है कि कश्मीर उनकी जागीर है। वैसे भी इन गुटों और खासकर नेशनल कांग्रेस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने कश्मीर को लूटा ही है। इस लूट-खोट से कश्मीर की जनता भी अवगत है। वह इससे भी परिचित है कि ये गुट जब सत्ता में होते हैं तो किस तरह देश, सविधान की बातें करते हैं और सत्ता से बाहर होने पर पाकिस्तान की भाषा बोलने लगते हैं। जम्मू-कश्मीर दे अभिन्न अंग हैं और इस ब कोई शक नहीं। जम्मू-कश्मीर दुश्मनों की बुरी नीयत से बच लिए न जाने कितने ही १३ सेना के जवान सीमा पर शग गए, पर उनकी शहादत का बैठे कुछ नेता मजाक उड़ा पीढ़ीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ बात कर रहे हैं। जो खु भारत को धमकी दे रही है विरोधी ताकतों को बल दे र अब वे विदेशी ताकतों को ह छुए यहां तक बोल गई कि “ने हमारा झांडा छीना”। बॉ नहीं खत्म हुई बल्कि मह भारतीय तिरंगा न उठाने का कर सीधे भारतीय सविधा चुनौती दी है। जबकि 25 1917 पूर्व केंद्रीय मंत्री अब्दुल्ला ने विवादित बयान दे कहा थी कि नई पीढ़ी के उआजादी के लिए लड़ रहे हैं बाद 16 नवम्बर 2017 अब कहा था कि :हम कब तक रहेंगे की (पीओके) हमारा

का न में को ने के तीय द हो ग में हैं। की आम देश हैं। देते कैतों यही । ने लान को रवरी रुक हुए तकी इके ब्रा ने रहते परस्सा है? 3 पीओके पाकिस्तान है और ये भारत 370 साल हो गये, वो पाकिस्तान है। अब्दुल्ला कह चुके हैं कि आज वे (भारत) दावा करते हैं कि ये भारत का हिस्सा है। तो इसे ले लीजिए, हम भी कहते हैं कि इसे ले लीजिए, हम भी देंखेंगे। वे कमज़ोर नहीं हैं और उन्होंने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। उनके पास भी परणामु बम है। युद्ध के बारे में सोचने से पहले हमें इंसान की तरह रहने के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन गुपकार गठबंधन के नेताओं को जितनी जल्दी यह समझ आए तो अच्छा कि यह देश किसी भी कीमत पर 370 की बापसी के लिए सहमत नहीं हो सकता, क्योंकि उसने अलगाव, अन्याय और आतंक के बीज बोने के अलावा और कुछ नहीं किया। परस्क अब्दुल्ला कितनी ही लीपापेती करें, देश उन्हें माफ नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने भारत की ओर आंख उठाने वाले चीन की खुली तरफ़दरी करके लोगों का सम्मान हमेशा के लिए खो दिया है और पीपुल्स पार्टी के नेताओं के और पाकिस्तान एवं रवैये से यह साफ विचारधारा एक तरह आतंकी और नक्सली है। इन दलों के लिए का मतलब केवल 370 कश्मीरी की पूर्व मुक्ति पीपुल्स डेमोक्रेटिक अध्यक्ष महबूबा मुफ्त झंडा एवं सर्वधान ले करके अलगावाद विचार के साथ ही पाकिस्तान सुर मिलाने का ही है। उन्होंने जम्मू-कश्मीर झंडा हाथ में लेकर आतंक की जमीन तैयार करके अनुच्छेद 370 को बांदा मांग करके उन कारणों साबित किया, जिनके लंबे समय तक न जरूर उहें जम्मू-कश्मीर देश के हितों की विकास कोई परवाह नहीं,

है। नेशनल डेमोक्रेटिक पारत विरोधी चीन समर्थक कि उनकी इस धमकी से चलता है कि पुरानी व्यवस्था बहाल न होने तक वह किसी चुनावी प्रक्रिया में भाग नहीं लेगी। वह ऐसा न करें तो उनकी मर्जी, लेकिन उन्हें इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं दी जा सकती कि वह लोगों को भड़काने के साथ राष्ट्र की भावनाओं को आहत करने का काम करें। यह दुर्योग नहीं कि महबूबा मुफ्ती उन फरूक अब्दुल्ला के साथ खड़ी हैं, जो चीन की मदद से अनुच्छेद 370 की वापसी का सपना देख रहे हैं। यह अच्छा हुआ कि इस तरह का बुरा सपना देखने वालों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह दो टूक जवाब दिया कि इस अनुच्छेद की वापसी किसी भी सूरत में नहीं होने वाली। यह जवाब इसलिए जरूरी हो गया था, क्योंकि पिछले दिनों कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चिंदबरम ने भी विभाजनकारी और भेदभाव को संरक्षण देने वाले अनुच्छेद 370 की तरफदारी की थी। चौंकि अब यह स्पष्ट है कि महबूबा मुफ्ती और फरूक अब्दुल्ला जैसे नेता अपने जहरीले और राष्ट्रविरोधी बयानों से कश्मीर का माहौल खराब करने का काम कर सकते हैं इसलिए उनकी गतिविधियों पर कड़ी निगाह रखी जानी चाहिए। वास्तव में अनुच्छेद 370 के खाते के बाद कश्मीर के सामान्य होते माहौल को जो भी बिगाड़ने का काम करे, उसके खिलाफ सख्ती बरतने में संकोच नहीं किया जाना चाहिए। यही नहीं महबूबा मुफ्ती और फरूक अब्दुल्ला पर आज नहीं बल्कि कई साल पहले ही देशद्रोह का आरोप लगना चाहिए था। यही कश्मीर घटी जब हिन्दुओं से खाली करवा ली गई थी, तभी इन पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए था। फरूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जैसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा दायर होना चाहिए। ये लोग दोबारा कश्मीर का लोकतंत्र लौटाएंगे। हमारी सरकार इनको डिफेंड करती है और महिमामंडन करती है। इसलिए इनका आजतक कुछ नहीं बिगड़ा।

सम्पादकाय

युनावी वैवसीन

ਕਾਜੂਨ ਬਨਾਨ ਵਾਲ ਹਾਂ ਕਾਜੂਨ ਕਾ ਧਾਰਿਆ ਤੜਾਨੇ ਕੇ ਸਥਾਨੇ ਬੜੇ ਜਿਰਮੇਦਾਰ

हैं। बिहार के विधानसभा चुनाव में वायदों की बाढ़ का अतहीन सिलसिला जारी है लेकिन केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा द्वारा जारी संकल्प पत्र में हर बिहारवासी को मुफ्त में कोरोना टीका उपलब्ध कराने के वायदे ने पूरे देशमें एक विवाद खड़ा कर दिया है। विपक्षी दल इसे कोरोना महामारी का राजनीतिकरण बता रहे हैं। निस्सदैह कोई राजनीतिक दल कोई भी वायदा कर सकता है लेकिन उसका नैतिक पक्ष भी देखना जरूरी है। इस समय पूरा देश इस महामारी से जूझ रहा है। ऐसे में एक राज्य के लिये अलग से बोट के बदले वैक्सीन की घोषणा निश्चित रूप से नैतिक दृष्टि से उचित नहीं है। दरअसल, इस महामारी में केंद्र और राज्यों में जैसा समन्वय महामारी से जूझने में देखने को मिला, वह प्रशंसनीय है। कई राज्यों से आवाजें उठने लगी हैं कि बिहार को वैक्सीन सिर्फ इसलिये मुफ्त देने की बात है कि वहां बोट लेना है। पूरा देश एक सदी बाद आयी महामारी से जूझ रहा है और वैक्सीन को लेकर हर कोई संवेदनशील है। हरेक की चिंता है कि उसे वैक्सीन मिल पायेगी या नहीं। तो ऐसे में किसी राजनीतिक घोषणा के जरिये वैक्सीन देने की बात करना एक भावनात्मक खिलवाड़ जैसा लगता है। यूं तो महामारी और अन्य संक्रामक रोगों के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर मुहिम केंद्र सरकार के नेतृत्व में ही चलायी जाती है। अखरने वाली बात यहध्य है कि पूरी दुनिया इस समय कोरोना महामारी से जूझ रही है। इस दौरान कई देशों में चुनाव भी हुए हैं लेकिन किसी भी देश में बोट के लिये वैक्सीन देने का वायदा नहीं किया गया। यहां तक कि दुनिया के सबसे ताकतवर लोकतंत्र और कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित अमेरिका में अगले महीने होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी कोई ऐसा वायदा नहीं किया गया। वैक्सीन के अलावा बिहार में वायदों की भरमार है। ज्यों-ज्यों चुनाव नजदीक आ रहा है, वायदों का शोर तेज होता जा रहा है। बिहार में साठ पीसदी आबादी 35 साल से कम की है। ऐसे में युवा और रोजगार वायदों के केंद्र में है।

की जनता को संबोधित किया। कोरोना काल में प्रधानमंत्री का जनता से यह सातवाँ संबोधन था। इस बार भी उन्होंने जनता को कोरोना के गंभीर खतरों से आगा ह कराते हुए कोरोना बचाव संबंधी गाइड लाइन का पूरी सख्ती से पालन करने का आवाहन किया। उन्होंने कोरोना के वर्तमान हालात पर चिंता जताते हुए देश की जनता से अपील की है कि कोरोना काल में लापरवाही न बरतें, बिना मास्क के घर से बाहर न निकलें। मोदी ने कहा है कि लॉकडाउन हटा है, कोरोना नहीं गया है। सामाजिक दूरी बनाए रखने पर जोर देते हुए उन्होंने यह भी कहा कि 2 गज की दूरी बनाए रखना और मास्क लगाना बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री ने मीडिया और सोशल मीडिया पर भी इस संबंध में जागरूकता लाने व कोरोना संबंधी नियमों का पालन करने के लिए जन-जागरण अभियान चलाने की जरूरत पर बल दिया। देश के मुख्याया के रूप में प्रधानमंत्री की उक्त चिंताएं स्वभाविक थीं। अब जरा बिहार के उप मुख्यमंत्री व भाजपा नेता सुनिए। सुशील मोदी ने वर्तमान रहे बिहार चुनावों में एस भाजपा को संबोधित करते हुए कि-आप कोरोना को बनाइये। इतनी बड़ी भीड़ देती लगता है कोरोना तो भाग कहाँ है कोरोना ? ये बिहार मित्रों, हम लोगों ने बेहतर इसे किया यह उसी का परिणाम है। बिहार में केवल साढ़े नौ सौ की मृत्यु हुई है जो दुख भाजपा के उपरोक्त दोनों शर्करों के संबोधन में फैला विरोधाभास नजर आता है। बिहार व मध्य प्रदेश के समय जमीनी हकीकत भर्ती है। सुशील मोदी के भाषण ऐसा प्रतीत होता है कि प्रधानमंत्री का संबोधन केवल विश्व संगठन तथा वैश्विक नेता अन्य देशों को यह जताने में लिए ही होता है कि भारत ने तृतीय में कोरोना का गंभीरता से मुकाबला कर रखा। परन्तु सुशील मोदी तो बिहार कोरोना संबंधी जमीनी हालत नजर अंदाज करते हुए सार्वजनिक भाषण दे रहे हैं जो बेहद गैर जिम्मेदाराना हैं ?

रेप उनका जानकारी का लाभउन होने की खबर आ गयी। वैसे भी बिहार के दो मंत्री कोरोना की भेंट चढ़ चुके हैं। इनमें पिछड़ा-अति पिछड़ा कल्याण मंत्री विनोद सिंह तथा बिहार के पंचायती राज मंत्री कपिल देव कामत का कोरोना से निधन हो चुका है। बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खुश्शीद उर्फ़ फिरोज अहमद की पत्नी जेबुन निसा (55) की कोरोना सक्रमण से मौत हो चुकी है। इसी प्रकार एक केंद्रीय मंत्री, अन्य कई राज्यों के मंत्री, विधायक कई आला अधिकारी यहाँ तक कि कोरोना से दूसरों की जान बचने वाले सैकड़ों डॉक्टर्स व स्वास्थ्यकर्मी इस गंभीर मर्ज की भेंट चढ़ चुके हैं। ऐसे में यदि कोई झूठे आत्म विश्वास का सहारा लेकर मात्र अपने राजनैतिक लाभ के लिए देश की जनता को गुमराह करता है या उसके सामने इस मर्ज की गंभीरता को कम करके आंकने की कोशिश करता है तो वास्तव में वह राजनेता नहीं बल्कि मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन तथा महामारी अधिनियम का मजाक उड़ाने का सबसे बड़ा यानी देश को सामास्क लगाने जैसा बाद 23 अक्टूबर चुनावी दौरे पर भी बिहार में चाहे वह सभाएँ हों या राहुल यादव अथवा निती हर जगह बे काबू डिस्ट्रेसिंग की उड़ना, मास्क लगाना जनता जानती ही न साफ नजर आ र राजनैतिक दल विए एक दूसरे पर अ करते दिखाई देते हैं के दिशा निर्देशों करने का आरोप दूसरे पर नहीं लगात है कि हम्माम में सभ तो भला हो ग सामाजिक कार्यक्र प्रताप सिंह का जिन उच्च न्यायलय की प्रमाण सहित ए याचिका दायर कर मंत्री नरेंद्र सिंह ते प्रदेश के पूर्व मुख्य नाथ के विरुद्ध को अधिनियम का उल्लं

लाराना निकल जाता है। इन स्वरूप दोनों नेताओं के विरुद्ध एफ आई आर दर्ज की जा सकी। अन्यथा प्रशासन के आला अधिकारी भी आसानी से इस स्तर के नेताओं के विरुद्ध कार्रवाई करने का साहस नहीं जुटा पाते। कोविड के शुरूआती दौर में ही कर्नाटक व महाराष्ट्र से ऐसे कई समाचार आए थे की एक ओर तो आम लोगों के शादी समारोह स्थगित कर दिए गए तो दूसरी ओर नेतागण पूरे धूमधाम से शादियाँ भी कर रहे थे और बर्थडे पार्टीयाँ भी मना रहे थे। कई आयोजनों में तो कर्नाटक के मुख्य मंत्री वाई एस येदुरप्पा भी शरीक हुए थे। देवगांड़ी के परिवार में भी इसी दौरान शादी समारोह हुआ था। परन्तु उच्च स्तर पर होने वाली ग्वालियर की पहली कार्रवाई है अन्यथा कहीं सामाजिक दूरी बनाए रखने संबंधी नियमों का उल्लंघन करने के लिए महाराष्ट्र के सतारा और शिर्डी में धार्मिक जुलूस निकलने को लेकर आईपीसी की धारा 188 और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 153 के तहत मामला दर्ज किया गया तो कहीं उत्तर प्रदेश में निम्नतरा दरमान पालना या परम महामारी के दौरान सामाजिक दूरी का पालन न करने के मामले में 2,000 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। कहीं मुहर्रम पर ताजीए निकालने वालों के विरुद्ध रासुका की कार्रवाई हुई। तो कहीं हिमाचल के कांगड़ा जिले के एक निजी अस्पताल को केवल इसीलिए सील कर दिया गया कि यहाँ सोशल डिस्टॉर्सिंग की धज्जियाँ उड़ाई जा रही थीं। निश्चित रूप से महामारी अधिनियम 1897 जनहित के लिए बनाया गया एक अधिनियम है जिसे कोविड जैसे अपरिहार्य अवसरों पर सख्ती से लागू किया जाता है। परन्तु क्या इस अधिनियम का पालन केवल आम लोगों को ही करना है ? कानून बनाने वाले क्या इस अधिनियम की पालना करने श्रेणी में नहीं आते ? बिहार के आम चुनाव, मध्य प्रदेश के उपचुनावों तथा राजनेताओं के पारिवारिक समारोहों की चकाचौध देखकर तो कम से कम ऐसा ही लगता है कि कानून बनाने वाले ही कानून की धज्जियाँ उड़ाने के सबसे बड़े जिम्मेदार हैं।

कोरोना संकट से उपजे आर्थिक संकुचन के बीच प्याज की आसमान छूती कीमतों ने उपभोक्ताओं की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं।

कहने का तो सरकार ने फरा तार पर कामता पर नियत्रण का कवायद शुरू कर दी है, मगर कीमतों में कमी होती नजर नहीं आ रही है। प्याज की कीमतों का सौ रुपये तक जाना खरीदारों का बजट बिगड़ रहा है, लोग खरीद में कटौती कर रहे हैं। दरअसल, अतिवृष्टि से कर्नाटक में प्याज की फसल को भारी नुकसान पहुंचा। इसी प्याज की आपूर्ति सितंबर-अक्टूबर में होती थी। उमीद है कि अक्टूबर के अंत तक महाराष्ट्र में होने वाली प्याज की फसल के बाजार में आने के बाद शायद कीमतों में कमी आए। आशंका है कि मौसम की मार के अलावा जमाखोरी की भी कीमतों की वृद्धि में भूमिका हो। अनुपान है कि हाल ही के कृषि सुधारों के क्रम में प्याज को जिस तरह से आवश्यक वस्तु कानून के दायरे से बाहर किया गया, उससे जमाखोरी को बढ़ावा मिला है। यही बजह है कि फैरी तौर पर सरकार ने जमाखोरी रोकने के लिये स्टॉक लिमिट लगा दी है। अब थोक विक्रेताओं के लिए स्टॉक लिमिट को 25 मीट्रिक टन किया गया है, वहीं खुदरा व्यापारियों के लिये यह मात्रा दो मीट्रिक टन है। लेकिन आयात किये जाने वाले प्याज पर यह लिमिट लागू नहीं होगी। वहीं दूसरी ओर संकट को देखते हुए सरकार ने प्याज के निर्यात पर रोक लगाने के बाद इसके आयात की अनुमति दी है ताकि मांग व आपूर्ति के संतुलन से प्याज की कीमतों को नियन्त्रित किया जा सके। लेकिन फिलहाल सरकार के कदमों का प्याज की कीमतों के नियन्त्रण पर बड़ा असर नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में प्याज की कीमतों में पड़ने वाले कारणों का समग्र विवेचन करना जरूरी हो जाता है। उन कारकों की पड़ताल भी जरूरी है जो हर साल प्याज की कीमतों में उफन ले आते हैं। दरअसल, भारत में मुख्यतरूप प्याज की तीन फसलें बाजार में आती हैं। अक्टूबर, दिसंबर और मार्च में आने वाली इन फसलों की आपूर्ति से कीमतों पर नियन्त्रण बना रहता है। लेकिन एक भी फसल के बाधित होने से बाजार में कीमतें उछल मारने लगती हैं। इधर एक घटक यह भी है कि मार्च में आने वाली रबी की प्याज में नमी की मात्रा कम होने के कारण किसान भी बड़े पैमाने पर इसका भण्डारण महाराष्ट्र में करने लगे हैं। इसकी आपूर्ति कर्नाटक के प्याज ने आने की स्थिति में अब दो गुड़ी है।

लिए के रही थी और अमेरिकी ध्वज की ओट से होते हुए ट्रंप मंच पर आये। स्पष्ट रूप से ट्रंप की एक बात जो लोगों को आकर्षित कर रही थी कि वे खुलकर मुसलमानों का विरोध कर रहे थे। काले और हिस्पेनिक्स लोगों के प्रति उनकी नफरत जाहिर थी। एडिसन नेवार्क अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास में स्थित है, इसीलिए भारतीय विमानों के ठहराव के लिए पहला गंतव्य स्थल है। यहां कारण है कि दशकों से एडिसन भारतीय प्रवासियों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है, खासकर उन लोगों के लिए जो गुजरात से आते हैं। आज 20 फीसदी आबादी यानी लगभग 99,000 लोग भारतीय-अमेरिकी हैं, उनमें से ज्यादातर गुजराती हैं। कुछ मौकों पर मैं एडिसन एनजे गया, लेकिन यह वैसा शहर नहीं है, जैसा कि रहने के लिए मैं चाहता हूं। यह मैला-कुचौला और शेर-शराबे वाला शहर है। यहां भारतीय सस्ते खाने-पीने के सामानों के लिए मोलभाव करते हैं। एडिसन के बारे में मेरे एक मित्र का कहना है कि यह अमेरिका का दूसरा हाथ है। पहला होबोकेन है, मतलब है, जो घेरे एनआरआई द्वारा जब जिक्र किया जाता है। निंदा के तौर पर विपछली गणना में अमेरिका से कम 28 लाख अमेरिकी जनगण मानचित्र से स्पष्ट है। अमेरिकी (आधिकारिक) एशियाई भारतीय स्थान विशेष पर सबै मैं जब भी अमेरिकी मुझे आश्र्य होता भारतीय-अमेरिकी मित्र केवल अन्य समाजीकृत होते हैं। झुंड में जाते हैं। भारतीय-अमेरिकी सठीक-ठाक संख्या एडिसन में यह जाएँ। अधिक है। अमेरिकी अमेरिकी उच्चतम रैंकिंग हिस्सा है। आमतौर पर हिस्सों में वेतनभोगी हालांकि, एडिसन में की पेशेवर आमदन अन्य भारतीय-अमेरिकी आय की तुलना में स्पष्ट तौर पर दिखती है।

हो. सभी भारतीयों का तो उसे स्व-गा जाता है. ऐरेका में कम ग देसी थे. -2000 क भारतीय-क तौर पर ग खुद को दृष्ट करते हैं. जाता हूँ तो कि हमारे रिवार और नी के साथ एक साथ अमेरिका में हों की एक लेकिन, वड़ा सबसे में भारतीय-य समूह का वे ज्यादातर कर्मचारी हैं. इस समुदाय की स्थिति कियों की कम है. यह है. पांच में अन्य क्षेत्र के भारतीयों की तरह अपने लोगों में जीना और सामाजिक जु़दाव खेना चाहते हैं. गुजराती स्वभाव से अधिक उद्यमी हाते हैं. अमेरिका में छ ह लाख वाले गुजराती समुदाय में पेशेवर लोगों की संख्या बहुत कम है. यहां कम खर्च वाले आश्रयग्रहों में आधे से अधिक के वे मालिक हैं. चूँकि, अमेरिका में रहनेवाले गुजरातीयों में बड़ी संख्या में पटेल उपनाम वाले लोग हैं, इन होटलों को लोग 'पोटेल्स' कहते हैं. अक्सर इन जगहों पर घटे के हिसाब से कमरे किये पर दिये जाते हैं एडिसन आरएसएस और रामभक्तों के लिए आदर्श केंद्र है, जो राजकोट या सूरत के बजाय इसे ज्यादा पसंद करते हैं. यह मोदी का देश है. सामान्य तौर पर भारतीय बहुत अधिक नस्लवादी, सांप्रदायिक और रंग भेदी होते हैं. हमारी राजनीतिक शुद्धता के स्पष्ट मानक नहीं है. हम रोजमरा के जीवन में नस्लवादी और दूसरों के लिए अपमानजनक आचरण करते हैं. अमेरिका में देसी समुदाय उससे ज्यादा अलग नहीं है. मीरा नायर की 1991 में आयी फिल्म 'मेरी देसी दुल्हन' की

सार समाचार



लुईस हैमिल्टन ने पूर्वगाल ग्रां प्री जीत कर महान माइकल शूमाकर का एकाई तोड़ा

नई दिल्ली एजेंसी। ब्रिटिश ड्राइवर लुईस हैमिल्टन ने पूर्वगाल ग्रां प्री जीतकर रविवार को फार्मूला 1 बन का नया इतिहास रच दिया। यह उनके कैरियर की 92वीं जीत थी और जब जमीनी के महान माइकल शूमाकर से आगे निकल गए हैं।

हैमिल्टन मर्सिडीज के अपने साथी ड्राइवर वाल्टर वोल्क्स ने 25.6 सेकंड आगे रहे। ड्रॉबुल के मैस्टर वैरस्टाम तीसरे स्थान पर रहे। हैमिल्टन ने सबसे तेज तैम निकालकर अतिरिक्त अंक भी बनाया और अब चैम्पियनशिप टेबल में बोड्यूस पर उनकी बढ़त 77 पॉइंट्स की हो गई है।

हैमिल्टन ने पहली एफवन रेस 2007 में जीती थी और पहला खिताब 2008 में अपने नाम किया। वह 2013 में मर्सिडीज से जुड़े और वहीं से उनका कैरियर परवान चढ़ा। वह पांच एफवन खिताब जीत चुके हैं जबकि शूमाकर के नाम सात खिताब हैं।

हरियाणा दिवस पर मून पिक माउंटेन को करेंगे फतेह

सोनीपत एजेंसी। हरियाणा दिवस (1 नवंबर) के उत्तरक्षय में पर्वतारोही रोहताश खिलेरी के नेटवर्क में एक दल 26 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में स्थित मून पिक माउंटेन की चोटी फतेह करने निकलेगा। इस चोटी पर उनकी स्टूडेंट टेलनवाली गांव से संजीतू बांगड़वा और दिसार से 12 साल की अनु यादव भी चढ़ाई करने रवाना होंगी। खेल मंत्री संदीप सिंह एवं रेस्टर एवं भाजपा नेता बवीता फौगट ने पर्वतारोही दल की छांडा टेकर रवाना होने से पहले कश्त्रा में खेल एवं युवा कल्याण राज्यसभा संदीप सिंह से खिलने पहुंचा था। खेल राज्यसभा संदीप सिंह ने पर्वतारोही दल को उनके अधियान के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रदेश के खिलाड़ियों के उनकी जरूरत के हिसाब से सुविधाएं देने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि हमारे खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए जिस भी सुविधा की जरूरत होगी, उसे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयास से खिलाड़ियों तक पहुंचाया जायगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवा खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान कर देश के नाम रोशन किया है। खिलाड़ियों के इस जब्ते पर पूरा राष्ट्र सलाम करता है। पर्वतारोही रोहताश खिलेरी ने बताया कि 29 अक्टूबर को लूट हिमाचल के मून पिक पर्वत पर चढ़ाई शुरू करेगा। एक नवंबर को हरियाणा दिवस के अवसर पर पर्वत की चोटी पर हरियाणा की ओर से ध्वज फहराने के साथ उनका यह अधियान पूरा होगा। खिलेरी दिसार के आदमपुर के गांव मालपुर के निवासी हैं और माउंट एवरेस्ट, अफ्रीका के माउंट किलिमज़ारा और यूरोप में सबसे ऊँचे पर्वत माउंट लूबुस को दो बार फतेह कर चुके हैं।

धोनी की पत्नी साक्षी बोली- कुछ लोग जीतते तो कुछ हारते हैं

सोनीपत एजेंसी। आईपीएल में तीन बार की चैम्पियन चेन्नई सुपर किंस रविवार को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलुरु को 8 विकेट से हारने के बाद भी प्ले-ऑफ की दौड़ से बाहर हो गई। क्वोटेक एक अन्य मैच में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियन्स को 8 विकेट से हरा दिया। जिससे चेन्नई की संभावना खमो गई। चेन्नई ने इस सीज़न में खेले 12 मैचों में से 8 मैच जीते हैं। जबकि 4 मैच जीते हैं। उसके बाट आईपीएल के इतिहास में पहली बार चेन्नई सुपर किंस एवं ऑफ की दौड़ में नहीं पहुंचे। 2008 में आईपीएल शुरू होने के बाद से वह तीन मैचों के बैंगलुरु के 11 मैचों के बाद तथा 14- 14 पॉटेंट है। जबकि 4 मैच जीते हैं। मैच में पहुंचना तथा है। वहीं चौथी टीम की दौड़ में सनराइजर्स हैदराबाद, कोलकाता नाइट राइडर्स किंस इलेवन पंजाब और चेन्नई सुपर किंस

मुंबई, दिल्ली और बैंगलुरु का एवं ऑफ में

पहुंचना तय वहीं मुंबई इंडियन्स, दिल्ली कैपिटल्स

और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलुरु के 11 मैचों के बाद

14- 14 पॉटेंट है। जबकि 4 मैच जीते हैं। मैच में पहुंचना तथा है। वहीं चौथी टीम की दौड़ में सनराइजर्स हैदराबाद, कोलकाता नाइट राइडर्स किंस इलेवन पंजाब और चेन्नई सुपर किंस

मुंबई, दिल्ली और बैंगलुरु का एवं ऑफ में

पहुंचना तय है। वहीं चौथी टीम की दौड़ में

सनराइजर्स हैदराबाद, कोलकाता नाइट राइ

डर्स किंस इलेवन पंजाब और चेन्नई सुपर किंस

मुंबई, दिल्ली और बैंगलुरु का एवं ऑफ में

पहुंचना तय है। वहीं चौथी टीम की दौड़ में

सनराइजर्स हैदराबाद, कोलकाता नाइट राइ

डर्स किंस इलेवन पंजाब और चेन्नई सुपर किंस

मुंबई, दिल्ली और बैंगलुरु का एवं ऑफ में

पहुंचना तय है। वहीं चौथी टीम की दौड़ में

सनराइजर्स हैदराबाद, कोलकाता नाइट राइ

डर्स किंस इलेवन पंजाब और चेन्नई सुपर किंस

मुंबई, दिल्ली और बैंगलुरु का एवं ऑफ में

पहुंचना तय है। वहीं चौथी टीम की दौड़ में

सनराइजर्स हैदराबाद, कोलकाता नाइट राइ

डर्स किंस इलेवन पंजाब और चेन्नई सुपर किंस

मुंबई, दिल्ली और बैंगलुरु का एवं ऑफ में

पहुंचना तय है। वहीं चौथी टीम की दौड़ में

सनराइजर्स हैदराबाद, कोलकाता नाइट राइ

डर्स किंस इलेवन पंजाब और चेन्नई सुपर किंस

मुंबई, दिल्ली और बैंगलुरु का एवं ऑफ में

पहुंचना तय है। वहीं चौथी टीम की दौड़ में

सनराइजर्स हैदराबाद, कोलकाता नाइट राइ

डर्स किंस इलेवन पंजाब और चेन्नई सुपर किंस

मुंबई, दिल्ली और बैंगलुरु का एवं ऑफ में

पहुंचना तय है। वहीं चौथी टीम की दौड़ में

सनराइजर्स हैदराबाद, कोलकाता नाइट राइ

डर्स किंस इलेवन पंजाब और चेन्नई सुपर किंस

मुंबई, दिल्ली और बैंगलुरु का एवं ऑफ में

पहुंचना तय है। वहीं चौथी टीम की दौड़ में

सनराइजर्स हैदराबाद, कोलकाता नाइट राइ

डर्स किंस इलेवन पंजाब और चेन्नई सुपर किंस

मुंबई, दिल्ली और बैंगलुरु का एवं ऑफ में

पहुंचना तय है। वहीं चौथी टीम की दौड़ में

सनराइजर्स हैदराबाद, कोलकाता नाइट राइ

डर्स किंस इलेवन पंजाब और चेन्नई सुपर किंस

मुंबई, दिल्ली और बैंगलुरु का एवं ऑफ में

पहुंचना तय है। वहीं चौथी टीम की दौड़ में

सनराइजर्स हैदराबाद, कोलकाता नाइट राइ

डर्स किंस इलेवन पंजाब और चेन्नई सुपर किंस

मुंबई, दिल्ली और बैंगलुरु का एवं ऑफ में

पहुंचना तय है। वहीं चौथी टीम की दौड़ में

सनराइजर्स हैदराबाद, कोलकाता नाइट राइ

डर्स किंस इलेवन पंजाब और चेन्नई सुपर किंस

मुंबई, दिल्ली और बैंगलुरु का एवं ऑफ में

पहुंचना तय है। वहीं चौथी टीम की दौड़ में

सनराइजर्स हैदराबाद, कोलकाता नाइट राइ

डर्स किंस इलेवन पंजाब और चेन्नई सुपर किंस

मुंबई, दिल्ली और बैंगलुरु का एवं ऑफ में

पहुंचना तय है। वहीं चौथी टीम की दौड़ में

सनराइजर्स हैदराबाद, कोलकाता नाइट राइ

डर्स किंस इलेवन पंजाब और चेन्नई सुपर किंस

मुंबई, दिल्ली और बैंगलुरु का एवं ऑफ में

पहुंचना तय है। वहीं चौथी टीम की दौड़ में

सनराइजर्स हैदराबाद, कोलकाता नाइट राइ

डर्स किंस इलेवन पंजाब और चेन्नई सुपर किंस

मुंबई, दिल्ली और बैंगलुरु का एवं ऑफ में

